एक्सप्रेस ट्रेन को लखनऊ तक चलाया जाए। साथ ही बांदा-खैराड़ा के बीच रेलवे क्रॉसिंग नं. सी 452 के आगे महोबा-दुरेड़ी रोड़ पर नया रेलवे फाटक बनाया जाए, जिससे नवोदय विद्यालय तथा एकलव्य डिग्री कॉलेज के छात्रों को आने-जाने में कठिनाई न हो।

मैं रेलमंत्री से मांग करता हूं कि इलाहाबाद-मुम्बई के बीच चलने वाली तुलसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को प्रतिदिन चलाए जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। बांदा-कानपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लखनऊ तक चलाया जाए और बांदा-खैराड़ा के बीच रेलवे क्रॉसिंग नं. सी 452 के आगे महोबा-दुरेड़ी रोड पर नया फाटक बनवाने की कृपा करें।

Demand to take strict measures to stop human trafficking in the country

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हमारे भारत में विषमताओं का बोलबाला इस हद तक बढ़ गया है कि भूमि, सम्पत्ति, पशुओं और साग-सब्जियों के साथ-साथ अब गरीब मजबूर व्यक्तियों और बच्चों की भी, धन अर्जित करने हेतु, खरीद-फरोख्त का घिनौना कार्य खुले आम हो रहा है। हद इतनी हो गयी है कि मासूम बच्चों, बच्चियों और विकलागों का बहुत ही थोड़ी रकम में घरेलू कामकाज, यौन-शोषण करने ओर भीख मंगवाने हेतु प्रयोग करते हैं। इस प्रकार खरीदे गए बच्चों के मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इससे पूरी मानवीय जातियां शर्मिदां हो रही हैं। वही चिंता का विषय यह भी है कि यह जो व्यक्तियों और बच्चों की खरीद-फरोख्त हो रही है, वह अधिकाशं दलित और पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों से संबंधित है। 67 वर्ष के बाद भी आर्थिक संकट इतना गंभीर है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। इस गंभीर समस्या पर देश की सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से पूरज़ोर अपील करता हूं कि शीघ्र ही इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए तथा इस खरीद-फरोख्त की अमानवीय प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।

Demand to review the merger of Public Sector Banks

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, the initiative to amalgamate certain public sector banks needs the rethink. Each and every bank, however small or big it may be, is having its own history, character, approach and leading to competition and also choice to account holders. Union Government and the Reserve Bank of India are now intending to encourage launching of new small banks. The banking needs of rural and urban population across the nation are manifold, since the delivery of various welfare benefits including the direct transfer besides linking with Aadhar. Some corporations at Union Government level and of State Governments like Electricity Boards have been divided into separate entities to look after the needs of generation, transmission and distribution and showing useful results. Within major banks, these were several subsidiary units to look after different needs. Keeping these factors and global experiences in view, I urge upon the Union Finance Ministry to revisit and evaluate deeply before any further move for merger of certain public sector banks.